भारत - हंगरी संबंध

वर्ष 1948 में भारत और हंगरी के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से इन दोनों देशों के बीच घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। ये संबंध सारगर्भित एवं बहुआयामी रहे हैं। हंगरी के लोग हंगरी के 1956 के बगावत में कानून एवं व्यवस्था के नियंत्रण में भारत की महती भूमिका के लिए भारत के प्रति काफी आभारी रहे हैं। सोवियत संघ के साथ भारत के हस्तक्षेपात्मक कार्रवाई से डा0 अर्पद गोंस्ज की जान बच सकी जो बाद में वर्ष 1990 से 2000 की अवधि के दौरान हंगरी के राष्ट्रपति रहे।हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण तथा समस्या रहित हैं।

वर्ष 1990 से, भारत और हंगरी के बीच अनेक करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिससे द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ हो सके हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं : इनमें दोहरा कराधान परिहार करार, द्विपक्षीय निवेश संरक्षण एवं संवर्धन करार, समाज सुरक्षा करार, स्वास्थ्य, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग संबंधी करार शामिल हैं। दोनों देशों ने वर्ष 1998 में राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगाठ का उत्सव मनाया

प्रधानमंत्री गयुर्कसानी ने वर्ष 2008 में राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगाठ के अवसर पर भारत की यात्रा की। भारत में आने वाले हंगरी के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों में वित्त मंत्री किंगा गोंस्ज (नवंबर 2006), वित्त मंत्री जैनोस वेरेस (जनवरी, 2007) पूर्व प्रधानमंत्री पीटर मेडग्येसे (जनवरी, 2007), संस्कृति एवं शिक्षा मंत्री इस्त्वान हिल्लर (अक्टूबर, 2007), कृषि मंत्री जोसेफ ग्राफ (जनवरी, 2008), रक्षा मंत्री इम्रे सजेकरेस (फरवरी, 2008), विदेश मंत्री जैनोस मार्तोन्यी (अक्टूबर, 1999), विदेश मंत्री पीटर बालाज्स (जनवरी, 2010) तथा हंगरी के नेशनल असेम्बली के स्पीकर, डा0 लास्ज्लो कोवेर (नवम्बर, 2012) शामिल हैं। प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने भारत का दौरा (16-18 अक्टूबर, 2013) को किया। उनके साथ बड़ा व्यावसायिक एवं सरकारी प्रतिनिधिमंडल भी था। विदेश मंत्री डा0 जानोस मार्तोन्यी ने असेम विदेश मंत्रियों की बैठक (असेम एफ एम एम 11) में भाग लेने के लिए भारत का दौरा (11-12 नवम्बर, 2013) में किया। विदेश एवं व्यापार मंत्री श्री पीटर स्जिजीजॉर्टो ने 20 मई, 2015 को मुंबई का दौरा किया। विदेश एवं व्यापार राज्य मंत्री डा. लासजलो सज़ाबो ने बंगलुरू में आयोजित दूसरे भारत - मध्य यूरोप व्यवसाय मंच के लिए एक कारोबारी शिष्टमंडल के साथ अक्टूबर 2015 में भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान हंगरी और कर्नाटक राज्य आर्थिक निगम के बीच एक एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत से संसदीय कार्य राज्य मंत्री (मई, 2011), विदेश मंत्री (असेम के लिए जून,2011), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (विश्व विज्ञान फोरम बैठक के लिए, नवम्बर, 2014) ने हंगरी का दौरा किया। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने साइबर स्पेस विषय पर आयोजित बुडापेस्ट सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुडापेस्ट (अक्टूबर 4-5, 2012) का दौरा किया। विदेश मंत्री ने हंगरी के राजदूतों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करने के लिए बुडापेस्ट का दौरा

किया और जल संसाधन मंत्री ने बुडापेस्ट जल शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुडापेस्ट का दौरा (7-10 अक्टूबर, 2013) किया। हरियाणा के 3 विधायकों के साथ हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री ने विश्व थोक बाजार संघ के सम्मेलन में भाग लेने के लिए 27 से 30 मई 2015 तक बुडापेस्ट का दौरा किया। पंजाब के उप मुख्य मंत्री ने एक कारोबारी शिष्टमंडल के साथ 30 जुलाई से 1 अगस्त 2015 के दौरान हंगरी का दौरा किया।

संयुक्त कार्यदल की हाल में निम्नलिखित बैठकें आयोजित हुई :-

(i) संयुक्त रक्षा समिति की 7वीं बैठक 11 और 12 मई 2014 को बुडापेस्ट में आयोजित की गई। सचिव (डी पी) ने भारत से 3 सदस्यीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।
(ii) संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति की बैठक नई दिल्ली में 14 अक्टूबर, 2013 को आयोजित हुई;
(iii) संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग की बैठक नई दिल्ली में 15-16 अक्टूबर, 2013 को आयोजित हुई; तथा
(iv) भारत - हंगरी संयुक्त रक्षा समिति की बैठक नई दिल्ली में 30 सितम्बर से 1 अक्टूबर की अवधि के दौरान आयोजित हुई ।
(v) भारत - हंगरी संयुक्त रक्षा समिति की बैठक 11 और 12 मई 2015 को हुई।

इसके पश्चात, हंगरी के प्रधानमंत्री श्री विक्टर ऑर्बन के 16-18 अक्टूबर, 2013 के दौरान राजकीय दौरे पर समझौता ज्ञापनों और आशय पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए:

1. वायु सेवा करार में संशोधन संबंधी आशय पत्र
2. भारत - हंगरी रणनीतिक अनुसंधान निधि के लिए आशय पत्र (2014-17 के दोरान प्रत्येक वर्ष के लिए 2 मिलियन यूरो का अधिक योगदान)
3. 2013-15 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
4. सूक्ष्म जैवीय एवं विकिरण चिकित्सीय संसूचन एवं संरक्षण की रक्षात्मक पहलुओं के क्षेत्र में सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन
5. खेल के क्षेत्र में सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन
6. चिकित्सा की परंपरागत प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन

वाणिज्यिक एवं आर्थिक संबंध

वर्ष 1990 में हंगरी में होने वाले परिवर्तन से पहले, भारत व्यापार एवं आर्थिक क्षेत्रों में हंगरी का एशिया में प्रमुख साझेदार था, यद्यपि इसने हंगरी के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का छोटा हिस्सा ही कवर कर पाया था। भारत में हंगरी की कंपनियों द्वारा 25 से अधिक संयुक्त उद्यम स्थापित किए गए। वर्ष 1990 में होने वाले व्यापक परिवर्तनों जैसे अर्थव्यवस्था का तेजी से निजीकरण, परंपरागत बाजारों का समाप्त होना एवं "पश्चिमी" निवेशों का आना के पश्चात भारत सहित अन्य देशों के साथ पुराना वाणिज्यिक संपर्क समाप्त हो गया। द्विपक्षीय व्यापार

जो 1980 के दशक में 100 से 200 मिलियन अमेरीकी डॉलर का था, वे 1990 के दशक के मध्य में जारी नहीं रखा जा सका। विगत कुछ वर्षों के दौरान भारत-हंगरी के बीच आर्थिक संबंध पुन: स्थापित हुए हैं, क्योंकि भारत और हंगरी दोनों देश वैश्विक रूप से एकीकृत हो गए हैं। हमारा व्यापार एवं निवेश सहयोग काफी बढ़ा है। वर्ष 2014 में द्विपक्षीय व्यापार 596 मिलियन अमरीकी डालर था। जनवरी से सितंबर 2015 के दौरान, व्यापार 440 मिलियन अमरीकी डालर था।

संयुक्त आर्थिक समिति (जे ई सी) ने आर्थिक सहयोग के संबंध में अंतरशासकीय विचार विमर्शों के लिए संस्थागत ढांचे की व्यवस्था की है। भारत की ओर से उद्योग विभाग नोडल एजेंसी है। फिक्की एवं हंगरी वाणिज्य मंडल के बीच हुए करार के तहत 1979 में स्थापित भारत तथा हंगरी की कंपनियों की संयुक्त व्यावसायिक परिषद निजी व्यवसायिक पक्षों के बीच सीधा संपर्क को बढ़ावा देता है। जे सी ई सी बैठक के चौथे सत्र का आयोजन 2016 में बुडापेस्ट में किया जाना है।

हाल के वर्षों में हंगरी में भारतीय निवेश में काफी वृद्धि हुई है। विभिन्न सेक्टरों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, औषधीय, पावर उपस्कर, ऑटो घटक एवं खाद्य प्रसंस्करण में निवेश हुआ है। हंगरी में टी सी एस, सन फार्मा, क्राम्पटन गीव्स, एस एम आर, बैकनी वाइपर्स, ओरियन तथा कॉसमोस प्रमुख निवेशकर्ता कंपनियां हैं। हंगरी में भारतीय निवेश 2 बिलियन अमेरीकी डॉलर का है जिससे हंगरी में लगभग 10,000 व्यक्तियों को रोजगार मिला है। अपोलो टायर्स द्वारा निवेश के कारण भारत 2014 में हंगरी में सबसे बड़ा निवेशक था, जो 475 मिलियन यूरो के कुल निवेश से ग्योंगीशलास्ज में एक ग्रीन फील्ड फैक्ट्री का निर्माण कर रहा है।

शिक्षा सहयोग :

भारत और हंगरी ने नवंबर 2014 में शिक्षा विनिमय कार्यक्रम (ई ई पी) पर हस्ताक्षर किए हैं। 2014-17 की अवधि के दौरान, ई ई पी ने उच्च शिक्षा संस्थाओं एवं प्रकाशनों, शैक्षिक सामग्रियों तथा पाठ्यक्रमों के आदान - प्रदान के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। यह संयुक्त अनुसंधानों एवं सम्मेलनों तथा अनुभवों की साझेदारी के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।

ई ई पी के तहत, हंगरी के ओर से भारतीय छात्रों एवं अनुसंधान अध्येताओं को हंगरी विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक एवं जीवन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, व्यवसाय तथा प्रबंधन और इंजीनियरी का अध्ययन करने के लिए 200 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। इसके बदले, भारत की ओर से अंग्रेजी एवं हिंदी भाषाओं में अध्ययन करने वाले अनुसंधान अध्येताओं तथा स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरेट स्तर के विभिन्न स्तरों पर अध्ययन कर रहे हंगरी के छात्रों के लिए 35 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी।

ई ई पी के ढ़ाचे के तहत, हंगरी की ओर से हंगरी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र से संबद्ध एक लेक्चरर को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली भेजा जाएगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग भारत और हंगरी के बीच संबंध की एक अहम कड़ी है। हंगरी भारत को सुविकसित अनुसंधान एवं विकास तथा 'ज्ञान' अवसंरचना वाला देश मानता है। इसके मद्देनजर, हंगरी ने हंगरी एकाडेमी ऑफ सांइसेज (एच ए एस) के तहत अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं का एक उत्कृष्ट नेटवर्क स्थापित किया है। वर्ष 2008 में भारत में हंगरी के प्रधान मंत्री के दौरे के दौरान हस्ताक्षर किए गए एक ढांचा करार के अंतर्गत, 2 मिलियन यूरो की भारत-हंगरी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी निधि की स्थापना की गई। इस करार में प्रतिवर्ष प्रत्येक देश की ओर से 1 मिलियन यूरो के अंशदान से एक निधि के सृजन की परिकल्पना की गई है। सुझाए गए क्षेत्रों में हरित रसायन (ग्रीन कैमिस्ट्री), जैव - चकिकत्सा तथा अंतरिक्ष (ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स) शामिल हैं। नवम्बर, 2011 में हंगरी में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री के दौरे के दौरान, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी निधि को प्रचालनात्मक बनाया गया। अक्टूबर, 2013 में भारत में हंगरी के प्रधानमंत्री श्री विक्टर ऑर्बन की यात्रा के दौरान, भारत - हंगरी रणनीतिक अनुसंधान निधि के लिए प्रत्येक देश का 2 मिलियन यूरो तक का संवर्धित योगदान संबंधी आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

कृषि

हंगरी के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान वर्ष 2008 में कृषि अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पादन, बागवानी एवं फसल कटाई उपरांत प्रबंधन (शीत श्रृंखला, कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि प्रबंधन सहित) को कवर करते हुए कृषि, पादप संगरोध एवं संरक्षण तथा पशुपालन के संबंध में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार के तहत गठित संयुक्त कार्यकारी समूह की नई दिल्ली में फरवरी, 2012 में एक बैठक हुई।

जल प्रबंधन :

जल संसाधन मंत्री ने अक्टूबर, 2013 में बूडापेस्ट जल शिखर सम्मेलन में भाग लिया तथा इस शिखर सम्मेलन के अवसर पर हंगरी के ग्रामीण विकास मंत्री, श्री संदारे फंजकास से मुलाकात की। जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को प्रारंभ करने के लिए दोनों के बीच गहन विचार - विमर्श हुआ। इस दिशा में आगे की कार्यवाही हेतु, दोनों पक्षों की ओर से विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है।

रक्षा

हंगरी के रक्षा मंत्रालय के साथ संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उप समूह संबंधी समझौता ज्ञापन को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। जे डी सी की 7वीं बैठक 11 और 12 मई 2015 को बुडापेस्ट में हुई तथा रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने पर सार्थक चर्चा हुई। सी बी आर एन उपस्कर एवं प्रशिक्षण, हवाई सी बी आर एन तथा प्रयोगशाला परीक्षा सुविधाओं के

क्षेत्र में सहयोग को अंतिम रूप देने के लिए एन बी सी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने हेतु, एक 3 सदस्यीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल ने 28 - 30 अप्रैल, 2014 के दौरान हंगरी का दौरा किया।

स्वास्थ्य

स्पा थेरापी में इसकी दीर्घ परंपरा एवं भारतीय संसकृति में गहरी रूचि के मद्देनजर, हंगरी में आयुर्वेद के संवर्धन की प्रबल संभावनाएं हैं। आयुष सूचना केंद्र जनवरी, 2014 से राजदूतावास में प्रचालनरत है। बुडापेस्ट में सितंबर, 2014 में एक अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें यूरोप के प्रतिभागियों ने भाग लिया। वर्ष 2008 में, हंगरी के प्रधानमंत्री के भारत में दौरे के दौरान स्वास्थ्य सेक्टर में सहयोग विषय पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें आयुर्वेद सहित इस सेक्टर में सहयोग हेतु आवश्यक विधिक एवं राजनीतिक ढांचे का प्रावधान है। अक्टूबर, 2013 में, भारत में हंगरी के प्रधनमंत्री श्री विक्टर ऑर्बन के दौरे के दौरान चिकित्सा की परंपरागत प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग विषय पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आयुष विषय के एक प्रोफेसर ने दिसंबर 2014 से डेबरेकन विश्वविद्यालय में आयुष संकाय के विभागाध्यक्ष का कार्यभार संभाला।

सांस्कृतिक संबंध :

हंगरी के प्रख्यात भारतविदों की पीढ़ियों ने भारत के प्रति जो आदर एवं श्रद्धा का व्यापक भाव स्थापित किया था, भारतीय संस्कृति, दर्शन, कला एवं आध्यत्मिक विचारों के प्रति हंगरी के लोगों में वही भाव सर्वदा परिलक्षित होता है। हंगरी के इन भारतविदों में कसोमा डि कोरोसी, ऑरेल स्टीन, एलिजाबेथ सस्स ब्रनर तथा एलिजाबेथ ब्रनर के नाम शुमार हैं। भारत की ओर से, रबिंद्रनाथ टैगोर एवं अमृता शेरगिल ने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। भारतविद्या विज्ञान ई एल टी ई विश्वविद्यालय में भारत - यूरोपीय अध्ययन विभाग के कार्य का हमेशा से एक प्रमुख हिस्सा रहा है। संस्कृत को औपचारिक रूप से 1873 में विश्वविद्यालय में अध्ययन के एक नियमित विषय के रूप में शामिल किया गया था। भारत एवं हंगरी के बीच द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत, आई सी सी आर वर्ष 1992 से इस विभाग में हिंदी विषय का एक अतिथि प्रोफेसर को प्रतिनियुक्त करता रहा है। भारतीय नृत्य, संगीत, योग तथा ध्यान के प्रति हंगरी के लोगों में व्यापक अभिरूचि देखने को मिलती है। हंगरी में 200 से अधिक योग केंद्र और भारतीय नृत्य एवं संगीत के लगभग 8 विद्यालय हैं। भारतीय सांस्कृतिक मंडलियां नियमित रूप से हंगरी का दौरा करती हैं।

अमृता शेरगिल सांस्कृतिक केंद्र :

15 अगस्त, 2014 को, बुडापेस्ट अवस्थित भारतीय संस्कृति केंद्र का नाम औपचारिक रूप से बदलकर 'अमृता शेरगिल सांस्कृतिक केंद्र' (ए एस सी सी) रख दिया गया। एएससीसी का नवम्बर, 2010 में औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। इस केंद्र में एक ऑडिटोरियम, एक पुस्तकालय एवं एक प्रदर्शनी हॉल है। एएससीसी में क्षेत्रीय सांस्कृतिक एवं अन्य समारोह

आयोजित किए जाते रहे हैं। एएससीसी द्वारा एक द्विमासिक पत्रिका 'अमृत' का प्रकाशन किया जाता है। हंगरी में विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग बढ़ रहा है। भारतीय क्लासिकल नृत्यों संगीत एवं योगा की कक्षाओं के अलावा, यह केंद्र आई सी सी तथा हंगरी तथा बोस्निया और हर्जेगोविना (बी आई एच) के विभिन्न भागों में प्रदर्शनियों, फिल्म महोत्सवों, भारत दिवसों और व्याख्यानों का आयोजन करता रहा है।

अध्येतावृत्त / छावृत्ति

भारत - यूरोपीय अध्ययनों को सुदृढ़ करने के लिए, भारत ने भारत - यूरोपीय अध्ययन विभाग ई एल टी ई विश्वविद्यालय में भारतविद्या विज्ञान एवं भारत अध्ययन पर टैगोर अनुसंधान अध्येतावृत्ति की स्थापना की है। इसी तरह "विदेश में हिंदी का प्रचार- प्रसार" योजना के तहत, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार केन्द्रीय हिंदी संस्थान आगरा में हिंदी सीखने वाले हंगरी के नागरिकों को प्रतिवर्ष दो छात्रवृत्ति स्लॉट प्रदान करती है। आई टी ई सी कार्यक्रम के तहत, हंगरी को प्रति वर्ष दस छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

भारतीय समुदाय :

हंगरी में रहने वाला 1000 व्यक्तियों का एक छोटा सा भारतीय समुदाय है जिसमें बुडापेस्ट, पेक्स, स्जेगेड एवं डेबरेकन स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 200 भारतीय विद्यार्थियों सहित अधिकांश सूचना प्रौद्योगीकी के पेशेवर हैं जो भारत - हंगरी संयुक्त उद्यमों में कार्यरत हैं। समय-समय पर, हमारे आदान- प्रदान कार्यक्रमों के तहत तीन सप्ताह से छः महीने की अवधि के दौरान अनुसंधानविदों एवं वैज्ञानिकों का आदान- प्रदान होता रहता है। इसके अतिरिक्त, कुछ भारतीय व्यक्तियों ने हंगरी के स्थानीय नागरिकों से शादी कर ली है और वहां ही स्थायी रूप से बस गए हैं।

उपयोगी संसाधन :

भारतीय दूतावास, बुडापेस्ट की वेबसाइट :
www.indianembassy.hu

भारतीय दूतावास, बुडपेस्ट फेसबुक :
https://www.facebook.com/IndiaInHungary

कलचर सेंटर का फेसबुक पेज :
https://www.facebook.com/ICCBudapestHungary

भारतीय दूतावास, बुडपेस्ट ट्विटर :
https://twitter.com/IndiaInHungary

*****

जनवरी, 2016